गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) महोदय, केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर के दो क्षेत्रीय केन्द्र हैं जो सिरसा और कोयम्बटूर में स्थित हैं ।

(ख) , से (घ) क्षेत्रीय केन्द्रों के लिए स्वीकृत स्टाफ और कार्यरत वैज्ञानिकों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

केन्द्र	स्वीकृत स्टाफ की संख्या	कार्यरत वैज्ञानिक
कोयम्बतूर	25	18
सिरसा	13	06

भा.कृ. अनु. परिषद् में वैज्ञानिकों के खाली पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है जिन्हें विज्ञापित किया जाता है ।

(ङ) आनुपातिक संख्या में वैज्ञानिकों, तकनीकी, प्रशासकीय और सहायक कर्मचारियों, उपकरणों एवं सिंचाई सुविधाएं प्रदान कर उक्त दोनों क्षेत्रीय केन्द्रो को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए गए हैं । टेक्नोलाजी के विकास और मूल अध्ययन के लिए भी केन्द्रों में चल रहे कपास अनुसंधान कार्य को समेकित किया गया है ।

विषय कृषि विज्ञान केन्द्र

2050. श्री ईश दत्त यादव : : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है देश में नये कृषि विज्ञान केन्द्र खोले गए है ;

(ख) यदि हां, तो उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इन केन्द्रों को कौन-कौन से स्थानों पर खोला गया है ;

(ग) अभी तक खोले गए कृषि विज्ञान केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने के क्या मानदण्ड है ?

गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी हां । [देखिए परिशिष्ट 167, अनुपत्र संख्या 27]

(ख) और (ग) सूची अनुपत्र में दी गयी है ।

(घ) नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अंतर्गत यह अनिवार्य है कि इसका कार्यान्वयन करने वाला संगठन कृषि विज्ञान केन्द्र के स्थान पर बिना किसी शुल्क के 50 एकड़ कृषि योग्य भूमि और अन्य नागरिक सुविधाएं जैसे पानी और बिजली उपलब्ध कराएं । फिर भी, ऐसे पिछड़े /पर्वतीय जिलों को वरीयता दी जाएगी जहां अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग रहते हैं ।

दिल्ली दुग्ध योजना का दिल्ली प्रशासन को सौंपा जाना

2059. श्री वीरेन जे. शाह : श्री राम जेठ मलानी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली दुग्ध योजना का भावी संचालन दिल्ली प्रशासन को सौंपने का निर्णय अन्तिम रूप से ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ;

(ग) क्या यह सच है कि वर्ष 1990 में सरकारिया समिति ने यह सिफारिश की थी कि इस योजना को सहकारी क्षेत्र में संचालित किया जाना चाहिए , और

(घ) यदि हां, तो उक्त सिफारिश को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :- (क) और (ख) जी हां । सरकार ने दिल्ली दुग्ध योजना को यथाशीघ्र दिल्ली प्रशासन को सौंपने का निर्णय लिया है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) दिल्ली में दूध का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में न होने के कारण यह निर्णय लिया गया है कि दिल्ली दुग्ध योजना, दिल्ली प्रशासन को सौंप दी जाए, जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ परामर्श करके इसकी भावी संरचना निर्धारित कर सकता है ।

वर्षा के जल पर निर्भर भूमि में खाद्यान्नों का उत्पादन

2060. **डा. जितेन्द्र कुमार जैन : श्रीमती सुषमा स्वराज :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में अधिकांश कृषि भूमि वर्षा के पानी पर निर्भर है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस प्रकार की भूमि पर चावल और गेहूं की अपेक्षा अन्य फसलों की खेती करना आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभदायक होगा ;

(ग) यदि हां, तो ऐसी भूमि पर कौन-कौन सी फसलों की खेती की जा सकती है ;

(घ) क्या सरकार ने वर्ष 1996-97 तक देश में ऐसे खाद्यान्नों के उत्पादन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो वे कौन-कौन से खाद्यान्न हैं तथा प्रत्येक खाद्यान्न के उत्पादन का लक्ष्य क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां ।

(ख) किसी फसल की लाभप्रदता कृषि जलवायु स्थितियां और बाजार मूल्य पर निर्भर करती है ।

(ग) मोटे अनाज, दालें, तिलहन तथा कपास जैसी फसलें अधिकतर वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उपजाई जाती है ।

(घ) और (ङ) योजना आयोग ने 1996-97 को समाप्त होने वाली आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए मोटे अनाज के मामले में 39 मिलियन मीटरी टन तथा दलहन के मामले में 17 मिलियन मीटरी टन का लक्ष्य निर्धारित किया है ।

Prices of Pulses

2061. SHRI RANJAN SAHU : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether the prices of pulses have gone up during the last two years;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government have formulated any development programme for pulses; and

(d) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM) : (a) and (b) The monthly average of Index Numbers of Wholesale Prices (Base 1981-82) of Pulses rose from 230.3 in April, 1991 to 253.7 in April, 1992 and to 256.4 (Provisional) in April, 1993.

(c) and (d) In order to increase the production of pulses the National Pulses Development Project (NPDP) is under implementation in 24 States and Union Territories of Andaman and Nicobar Islands and Delhi. Under the programme, assistance is provided for seeds, conducting demonstrations, plant protection measures, improved farm implements, training of extension workers, etc. The pattern of assistance under the Project is 75:25 basis between Government of India and States. The outlay for the Project for the year 1993-94 is Rs. 28.00 crore as Central share.

State Farms Corporation of India

2062. SHRI MENTAY PADMANABHAM : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are serious allegation of misuse of funds in the State Farms Corporation of India;